राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड ने नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और राज्य निर्वाचन आयुक्तों (SECs) के ऐतिहासिक राष्ट्रीय राउंड टेबल सम्मेलन में प्रतिभाग किया;

नई दिल्ली | 24 फरवरी, 2026

राज्य निर्वाचन आयोग (SEC), उत्तराखंड ने 24 फरवरी, 2026 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और राज्य निर्वाचन आयुक्तों (SECs) के ऐतिहासिक राष्ट्रीय राउंड टेबल सम्मेलन में प्रतिभाग किया। 27 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त, श्री ज्ञानेश कुमार ने माननीय निर्वाचन आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में की।

"राष्ट्रीय घोषणा 2026"

निर्वाचन प्रबंधन, क्षमता संवर्धन एवं संसाधन साझा किये जाने हेतु सहकारी संघवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, यह घोषणा निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित है:

- **मतदाता सूची:** मतदाता सूचियों की "लोकतंत्र की आधारशिला" के रूप में स्वीकारोक्ति।
- **संस्थागत सामंजस्य:** प्रौद्योगिकी (ECINET), ईवीएम (EVM) और IIIDEM की विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं ढांचे को साझा करने के लिए परस्पर स्वीकार्य रूपरेखा तैयार करना।
- **विधिक सामंजस्य:** लॉजिस्टिक सुगमता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए पंचायत और नागर निकाय निर्वाचनों से संबंधित विधियों को संसद और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन की विधियों के साथ समन्वित करना।

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड का महत्वपूर्ण विषयों पर सम्बोधन:

सम्मेलन के दौरान, माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखंड श्री सुशील कुमार द्वारा सभा को सम्बोधित किया गया, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में गत वर्ष के स्थानीय निकाय निर्वाचनों का विवरण साझा किया और ECINET, मतदाता सूची, प्रशिक्षण सुविधाओं को साझा किये जाने के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला:

- **मतदाता सूची डेटाबेस प्राप्ति हेतु 60 दिन पूर्व अनुरोध:** राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) उत्तराखंड ने उन **लॉजिस्टिक और विधिक कठिनाइयों** पर प्रकाश डाला, जिसके अंतर्गत वर्तमान में आयोग को विधानसभा नामावली डेटाबेस के लिए **60 दिन पहले** अनुरोध करना अनिवार्य है। इस समय अंतराल (time-lag) के कारण, इस बीच विधानसभा मतदाता सूची में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार SEC की मतदाता सूची को समय पर अपडेट करने में कठिनाइयां सामने आती हैं।

- **API-आधारित डिजिटल हैंडशेक:** आयोग ने ECI और SEC डेटाबेस के बीच **"डिजिटल हैंडशेक"** (API-आधारित एकीकरण) तंत्र की बात रखी। यह **"डिजिटल गतिशीलता" (Digital Dynamism)** सुनिश्चित करेगा, जिससे स्थानीय निकाय मतदाता सूची में विधानसभा नामावली के रियल-टाइम अपडेट स्वतः परिलक्षित हो सकेंगे।
- **गत वर्ष के स्थानीय निकाय निर्वाचन:** आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव (2024-25) और पंचायत चुनाव (जुलाई 2025) के आंकड़े साझा किए, जिसमें 12 पर्वतीय जिलों में **69.16%** का मतदान प्रतिशत रहा।
- **पर्वतीय क्षेत्र और आपदा प्रबंधन:** उत्तराखण्ड आयोग निर्वाचन में प्रत्येक जनपद में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जिला आपदा शमन और आपदा प्रबन्धन योजना के साथ मिलकर विशिष्ट आपदा आकास्मिक योजना (Disaster Contingency Plan) का उपयोग किये जाने पर बल दिया, जिसमें कठिन मौसम की परिस्थितियों में ऊंचाई वाले दूरदराज के मतदान स्थलों के लिए आपदा प्रतिवादन कर्मियों की तैनाती सम्मिलित है।

भविष्य की कार्ययोजना

सम्मेलन का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि यह राष्ट्रीय राउंड टेबल सम्मेलन अब प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड आयोग द्वारा दिए गए सभी सुझावों का भारत निर्वाचन आयोग के विधिक और तकनीकी अधिकारियों की एक संयुक्त टीम द्वारा अध्ययन किया जाएगा। अगले तीन महीनों में एक राज्य-विशिष्ट रोडमैप तैयार किए जाने की संभावना है।